हिन्दी पाक्षिक

# सेमन्या कण्वघाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-14 अंक-01 हरिद्वार, रविवार, 15 नवम्बर, 2026 मूल्य-दो रूपया मात्र पृष्ठ-12

## मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आधुनिक 'कामधेनु लोक' गौशाला का लोकार्पण किया



**हरिद्वार ।** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सप्तऋषि, हरिद्वार स्थित कामधेनुलोक भवन में आधुनिक 'कामधेनुलोक' गौशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला द्वारा गौसेवा, गोवंश संरक्षण एवं मानव सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कामधेनुलोक जैसी पहल गौसंरक्षण के साथ भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गौ माता का विशेष स्थान है। हमारी परंपरा में गौ माता को सर्वदेवमयी माना गया है। गांवों में आज भी गौ माता को परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा की जाती है। उन्होंने कहा कि गौसेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक जीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी अभिन्न अंग है। गौसंरक्षण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला की सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2010 में मात्र 11 गोवंश के संरक्षण से शुरू हुआ यह अभियान आज व्यापक स्वरूप ले चुका है। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में पांच राज्यों में 15 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से 35 हजार से अधिक गोवंश की सेवा और संरक्षण किया जा रहा है। अकेले हरिद्वार में हजारों निराश्रित, घायल, वृद्ध एवं बीमार गोवंश को आजीवन संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में नंदी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था द्वारा गौसेवा के साथ मानव सेवा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। संस्था की पांच हाइड्रोलिक गौसेवा एम्बुलेंस के माध्यम से अब तक पांच हजार से अधिक गोवंश को बचाकर सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाया गया है। गोवंश के लिए चिकित्सा, चारे एवं पौष्टिक आहार की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा प्रतिदिन 1500 से अधिक जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने के साथ जरूरतमंद परिवारों को राशन एवं चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण की ऐसी पहल समाज के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में गौसंरक्षण, देसी नस्लों के संवर्धन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार भी गौशालाओं के आधुनिकीकरण, निराश्रित गोवंश की देखरेख तथा गौ आधारित आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गौपालन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बद्री गाय के शुद्ध घी एवं अन्य दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं। अकेले चमोली जनपद में तीन ग्रोथ सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।

इन प्रयासों से स्थानीय पशुपालकों को बेहतर अवसर मिलने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश के 72 पंजीकृत एवं 9 अनुबंधित गोसदनों के माध्यम से 16 हजार से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही ग्राम्य गोसेवक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, ताकि गांवों के स्तर पर भी गौसेवा एवं गौसंरक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि शहरी विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से प्रदेश में 63 स्थानों पर गौशाला निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की गई है। इन स्थानों पर गौशालाओं के निर्माण की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ने से गोवंश, विशेषकर नंदियों की पारंपरिक उपयोगिता में परिवर्तन आया है।

ऐसे में गौसंरक्षण के लिए दीर्घकालिक एवं व्यावहारिक समाधान विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल गौशालाओं का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गोवंश को प्राकृतिक खेती, जैविक खाद, बायोगैस और कृषि नवाचारों से जोड़ना भी जरूरी है। इससे गौसंरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसेवा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार गौसंरक्षण से संबंधित कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि गोवंश के प्रति क्रूरता एवं गौहत्या जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार देश की आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र है। कामधेनुलोक जैसी परियोजनाएं हरिद्वार की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को और समृद्ध करेंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को भव्य, दिव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार व्यापक तैयारियां कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क एवं यातायात व्यवस्था, नए पुलों, संपर्क मार्गों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के दृष्टिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ आधुनिक तकनीक आधारित भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत, स्वच्छता, सुव्यवस्था और अतिथि सत्कार का सुखद अनुभव लेकर लौटें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। गौसंरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को एक-दूसरे से जोड़ना भी इसी संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कामधेनुलोक गौशाला गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं आध्यात्मिक पर्यटन के समन्वय का एक अनुकरणीय मॉडल बनेगी। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला से जुड़े सभी संतों, सेवकों, पदाधिकारियों एवं सहयोगियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मदन कौशिक एवं प्रदीप बत्रा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एवं प्रीतम सिंह पंवार, महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास महाराज, स्वामी आत्मानंद महाराज सहित अनेक संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

## पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 29 नवंबर को होगी

**हरिद्वार ।** उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा 29 नवंबर (रविवार) को प्रदेश के सभी 13 जिलों के 18 नगरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में दोपहर दो से शाम चार बजे तक सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट श्रह्यष्.ह्वद्म.द्श1.द्बठ्ठ से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।परीक्षा केंद्र बदलने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

## होमगार्ड में चयनित सभी 12 अभ्यर्थीयो को ग्राम प्रधान ने सम्मानित किया

**हरिद्वार ।** ग्राम पंचायत रसूलपुर मीठीबेरी में गुरुवार को खुली बैठक आयोजित की गई। इसमें होमगार्ड भर्ती में सफल हुए गांव के सभी 12 युवकों को सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान कमलेश द्विवेदी ने युवकों और उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवकों का चयन होना गांव के लिए गौरव की बात है। बैठक में स्वच्छता कार्यों के लिए ग्रामीणों से सहयोग और सेवा शुल्क देने की अपील की गई। सड़क निर्माण, पुलिया, विद्युत पोल, पथ प्रकाश व्यवस्था और पेंशन से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनुज कुमार, विनय सिंह, सोहन सिंह, संध्या, सुनील, अरविंद, सुरेंद्र रावत सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

## कुंभ-2027: पुलों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूरा करने पर मेला प्रशासन का विशेष जोर

**हरिद्वार ।** कुंभ मेला-2027 की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गंगा घाटों के निर्माण एवं मरम्मत से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने के बाद अब मेला प्रशासन का विशेष जोर विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन पुलों व अन्य लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने पर है। मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। इसके तहत वरिष्ठ अधिकारी लगातार कार्यस्थलों पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के साथ ही उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके।

इसी क्रम में बुधवार को अपर मेलाधिकारी श्री दयानंद सरस्वती ने



खड़खड़ी में सूखी नदी पर निर्माणाधीन डबल लेन स्टील गर्डर पुल तथा दक्षद्वीप में एस्केप चैनल पर बन रहे पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की वर्तमान प्रगति की जानकारी लेते हुए विभिन्न चरणों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। इसके लिए कार्यदायी संस्थाएं पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करते हुए पूरी क्षमता एवं दक्षता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ ही गुणवत्ता के मानकों का भी पूरी गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि तैयार होने वाले पुल कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों के आवागमन के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साबित हों। अपर मेलाधिकारी ने पुराने दिल्ली-नीति पास मार्ग पर चल रहे सड़क सुधारीकरण एवं फुटपाथ निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री योगेश कुमार को निर्देशित किया कि मार्ग के जिन हिस्सों में सीसीटीवी नेटवर्क की भूमिगत केबल डालने तथा सीवरेज लाइन से संबंधित कार्य शेष होने के कारण सड़क सुधारीकरण का कार्य लंबित था, वहां अब संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं।

# सम्पादकीय

## तेरह वर्षों का सफर -संघर्ष, संकल्प और पाठकों का अटूट विश्वास

**समय के थपेड़ों के बीच निरंतर आगे बढ़ती पत्रकारिता की यात्रा, पाठकों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी**

प्रिय पाठकों, सादर अभिवादन!

15 नवम्बर 2013... यह वह तारीख है, जिसने एक विचार को संकल्प और संकल्प को पत्रकारिता के एक सफर में बदल दिया। इसी दिन से सेमन्या कण्वघाटी हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र की यात्रा प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य स्पष्ट था—समाज की आवाज बनना, जनसरोकारों को प्राथमिकता देना, सच को निर्भीकता से सामने रखना और पत्रकारिता को आम आदमी की उम्मीदों से जोड़ना।

यह सफर कभी आसान नहीं रहा। समय के साथ अनेकानेक उतार-चढ़ाव आए। कभी परिस्थितियों ने परीक्षा ली तो कभी संसाधनों की चुनौतियों ने रास्ता कठिन बनाया। समय बदला, परिवेश बदला, पत्रकारिता के तौर-तरीके बदले, लेकिन एक संकल्प हमेशा कायम रहा—पाठकों के विश्वास को बनाए रखना और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना।

किसी समाचार पत्र की वास्तविक पहचान उसके पन्नों की संख्या, प्रसार के आंकड़ों या आकर्षक शीर्षकों से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान उन विचारों, मुद्दों और सरोकारों से होती है, जिन्हें वह समाज के सामने रखता है। हमने भी अपने इस सफर में हमेशा यही प्रयास किया कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की आवाज को स्थान मिले। जनसमस्याओं को मंच मिले, शासन-प्रशासन तक जनता की बात पहुंचे और सकारात्मक बदलाव की संभावनाओं को मजबूती मिले।पत्रकारिता का रास्ता चुनना जितना सरल दिखाई देता है, उस पर निरंतर चलते रहना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। विशेषकर क्षेत्रीय पत्रकारिता में सीमित संसाधनों के बीच जनहित के मुद्दों को जीवित रखना, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। हमने भी इस यात्रा में कई कठिन दौर देखे, लेकिन हर कठिनाई ने कुछ नया सिखाया और हर चुनौती ने आगे बढ़ने का हौसला दिया।आज पत्रकारिता एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां सूचना की गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने समाचारों की दुनिया को व्यापक बनाया है। एक ओर सूचनाओं तक आम आदमी की पहुंच आसान हुई है, वहीं दूसरी ओर भ्रामक खबरों, अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं की चुनौती भी बढ़ी है। ऐसे समय में पत्रकारिता की विश्वसनीयता, तथ्यपरकता और जिम्मेदारी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

हमारा मानना है कि पत्रकारिता किसी विचारधारा की बंधक नहीं होनी चाहिए। उसका पहला और अंतिम सरोकार जनहित होना चाहिए। सत्ता से सवाल पूछना पत्रकारिता का दायित्व है तो समाज की सकारात्मक उपलब्धियों को सामने लाना भी उसकी जिम्मेदारी है। जहां गलत है, वहां सवाल उठना चाहिए और जहां अच्छा कार्य हो रहा है, वहां उसकी सराहना भी होनी चाहिए। आलोचना और प्रशंसा दोनों का आधार तथ्य और निष्पक्षता होनी चाहिए।

सेमन्या कण्वघाटी ने अपने इस सफर में पाठकों को हमेशा केंद्र में रखा है। हमारे लिए पाठक केवल समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि इस पूरी यात्रा का सहभागी है। पाठकों का स्नेह, सुझाव, आलोचना और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही वह शक्ति है, जिसने अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस समाचार पत्र को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।हम यह भी स्वीकार करते हैं कि इस यात्रा में बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ करना शेष है। समय के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। बदलते दौर की आवश्यकताओं को समझते हुए समाचार पत्र की सामग्री, प्रस्तुति और जनसरोकारों को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास जारी रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि ग्रामीण अंचलों, पहाड़ की समस्याओं, युवाओं के भविष्य, महिलाओं के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए।हमारा विश्वास है कि क्षेत्रीय पत्रकारिता ही समाज की वास्तविक धड़कनों को सबसे करीब से महसूस करती है। गांव की सड़क से लेकर राजधानी की नीतियों तक, आम नागरिक की परेशानी से लेकर शासन की योजनाओं तक, हर उस विषय को सामने लाना जरूरी है जिसका सीधा संबंध जनजीवन से है।आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 15 नवम्बर 2013 से शुरू हुई यह यात्रा अनेक स्मृतियों, अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों से भरी दिखाई देती है। लेकिन हमारे लिए यह किसी पड़ाव पर पहुंचकर ठहर जाने का अवसर नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का समय है।

अंत में अपने सभी पाठकों, शुभचिंतकों, सहयोगियों और उन सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस यात्रा में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया। आपका विश्वास ही हमारी प्रेरणा है और आपकी अपेक्षाएं ही हमारी जिम्मेदारी।

हमारा संकल्प स्पष्ट है—समय और परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदलें, पाठकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कायम रहेगी। हम समाचार पत्र को सदैव पाठकों के लिए समर्पित रखते हुए जनहित, जनभावनाओं और सामाजिक सरोकारों की आवाज बुलंद करते रहेंगे।

क्योंकि हमारा विश्वास है कि समाचार पत्र केवल कागज पर छपे शब्दों का संग्रह नहीं होता, वह समाज के विश्वास, विचारों और उम्मीदों का दस्तावेज होता है।

इसी विश्वास के साथ...

आपका अपना समाचार पत्र, आपकी आवाज और आपके विश्वास का साथी—सेमन्या कण्वघाटी।

सादर आभार!

**अवनीश कुमार**
**सम्पादक**
**सेमन्या कण्वघाटी हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र**

# डिजिटल क्रांति के बीच कायम नकदी का आकर्षण

**-डॉ. प्रियंका सौरभ**



भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में 8 नवंबर 2016 की रात एक ऐसा निर्णय लिया गया, जिसने देश के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा केवल मुद्रा परिवर्तन नहीं थी, बल्कि इसे काले धन, नकली नोटों, भ्रष्टाचार और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण पर प्रहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उस समय प्रचलित मुद्रा के कुल मूल्य का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा इन दोनों नोटों में था। आज दस वर्ष बाद जब इस फैसले का मूल्यांकन किया जा रहा है, तब एक महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आता है। देश में डिजिटल भुगतान का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, लेकिन नकदी का प्रचलन भी लगातार बढ़ा है। यही विरोधाभास नोटबंदी की वास्तविक उपलब्धियों और सीमाओं को समझने की कुंजी है।

नोटबंदी के बाद सामने आया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में देखने को मिला। हालांकि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की शुरुआत अप्रैल 2016 में नोटबंदी से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन नोटों की अचानक कमी ने लोगों को डिजिटल भुगतान के विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड आधारित भुगतान धीरे-धीरे आम जीवन का हिस्सा बन गए। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 241 अरब से अधिक लेन-देन दर्ज किए गए। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, सेवा प्रदाताओं और आम उपभोक्ताओं के बीच इसकी स्वीकार्यता ने भारतीय भुगतान व्यवस्था में व्यापक बदलाव को दर्शाया है। यह कहना उचित होगा कि नोटबंदी ने डिजिटल भुगतान को अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान की।

इस फैसले का एक अन्य परिणाम बैंकिंग व्यवस्था में जमा राशि की अस्थायी वृद्धि के रूप में सामने आया। पुराने नोट बैंकों में जमा होने से बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ी और वित्तीय संस्थाओं को असामान्य लेन-देन की पहचान करने के अवसर मिले। पहले बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहने वाली कई नकदी जमाओं का विवरण उपलब्ध हुआ। इससे आयकर विभाग को संदिग्ध लेन-देन की जांच, कर चोरी की पहचान और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त पुराने मूल्यवर्ग के नकली नोट तत्काल अमान्य हो गए। इससे मौजूदा नकली मुद्रा नेटवर्क को झटका लगा। नोटबंदी ने बैंकिंग सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और वित्तीय जागरूकता के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद नोटबंदी के आर्थिक परिणाम कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न काले धन की वापसी और उसकी वास्तविक रोकथाम से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, विमुद्रीकृत मुद्रा का लगभग 99.3 प्रतिशत हिस्सा वापस बैंकिंग प्रणाली में आ गया। लगभग 15.41 लाख करोड़ रुपये की अमान्य घोषित मुद्रा में से करीब 15.31 लाख करोड़ रुपये बैंकों में लौट आए। यह आंकड़ा उस अपेक्षा के विपरीत था, जिसके अनुसार बड़ी मात्रा में काला धन नकदी के रूप में होने के कारण स्वत: समाप्त हो जाएगा। यह जरूर है कि बैंक में जमा हुई पूरी राशि को वैध नहीं माना जा सकता, लेकिन इससे स्पष्ट हुआ कि नोटबंदी के माध्यम से स्थायी रूप से समाप्त हुई नकदी अपेक्षाकृत बहुत कम थी। इसका मूल कारण यह है कि काला धन केवल नकदी के रूप में नहीं रखा जाता। उसका बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति, सोना, बेनामी संपत्तियों, विदेशों में जमा धन, फर्जी कंपनियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेशित रहता है। इसलिए केवल बड़े नोटों को प्रचलन से बाहर कर देना काले धन की पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए कर व्यवस्था में पारदर्शिता, संपत्ति के लेन-देन की निगरानी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

नकदी पर निर्भरता का बने रहना भी नोटबंदी की सीमाओं को उजागर करता है। नवंबर 2016 के आसपास प्रचलन में मुद्रा लगभग 17.77 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर लगभग 43.16 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि डिजिटल भुगतान के विस्तार के बावजूद नकदी भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कारोबारियों, दैनिक मजदूरों और सीमित इंटरनेट सुविधा वाले लोगों के लिए नकदी आज भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि डिजिटल भुगतान असफल रहा, बल्कि यह स्पष्ट करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल माध्यम दोनों की अपनी उपयोगिता है। नोटबंदी का सबसे गंभीर प्रभाव असंगठित क्षेत्र पर पड़ा। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, कृषि मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और सूक्ष्म उद्यमों को अचानक नकदी की कमी का सामना करना पड़ा। अनेक कारोबारों की बिक्री घटी, उत्पादन प्रभावित हुआ और कुछ प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। दैनिक मजदूरी पर निर्भर लोगों की आय में कमी आई। ग्रामीण बाजारों में सामान्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हुईं। देश की अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों और असंगठित क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह व्यवधान केवल कुछ दिनों की समस्या नहीं था, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिणाम सामने आए।

इसके अतिरिक्त नई मुद्रा में भी नकली नोटों की मौजूदगी सामने आई। इससे स्पष्ट हुआ कि नकली मुद्रा की समस्या केवल पुराने नोटों को अमान्य करने से समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए बेहतर सुरक्षा विशेषताओं, खुफिया तंत्र, सीमा निगरानी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसी प्रकार अचानक लिए गए आर्थिक निर्णयों के कारण उपभोग, उत्पादन और अल्पकालिक आर्थिक विकास पर भी दबाव पड़ा। आज आवश्यकता इस बात की है कि काले धन के विरुद्ध लड़ाई को केवल नकदी तक सीमित न रखा जाए। कर चोरी रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई, संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता और विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट सुविधा, सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता सुनिश्चित करनी होगी। छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरल कर व्यवस्था, आसान ऋण और कम अनुपालन बोझ के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना चाहिए। नोटबंदी के दस वर्ष बाद यह स्वीकार करना होगा कि इस फैसले ने भारत में डिजिटल भुगतान और बैंकिंग लेन-देन की पारदर्शिता को गति दी, लेकिन काले धन को समाप्त करने और नकदी पर निर्भरता घटाने के अपने व्यापक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि आर्थिक बदलाव केवल मुद्रा की प्रकृति बदलने से नहीं आते।

उनके लिए मजबूत संस्थाएं, जवाबदेह शासन, प्रभावी कर व्यवस्था, वित्तीय समावेशन और निरंतर सुधार आवश्यक हैं। भारत की डिजिटल क्रांति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी वास्तविक सफलता केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि आर्थिक पारदर्शिता, सामाजिक समावेशन और आम नागरिक के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों से मापी जानी चाहिए।

# उत्तराखंड पंचायतीराज का दूसरा नाम बनीं IAS निधि यादव, केंद्र में लगातार दूसरी बार मिली बड़ी जिम्मेदारी

**-निदेशक रहते 400 से अधिक नियुक्तियां, पंचायतों का डिजिटलीकरण और 25 साल बाद ADO से जिला पंचायत राज अधिकारी पदों पर पदोन्नति; पीडीआई रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर**

देहरादून। उत्तराखंड में पंचायतीराज व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विभागीय प्रशासन से लेकर पंचायतों के डिजिटलीकरण, कार्मिक व्यवस्था में सुधार, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन और पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास तक अनेक पहल की गईं। उनके कार्यकाल में विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां हुईं, पंचायतों को डिजिटल



व्यवस्था से जोड़ने का काम आगे बढ़ा और पिछले 25 वर्षों में पहली बार सहायक विकास अधिकारी (ष्ठह्व पंचायत) से जिला पंचायत राज अधिकारी के पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुला। पंचायतों में महिला सभा और बाल सभा के गठन जैसी पहल ने स्थानीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी दौरान पंचायत विकास सूचकांक (PDI) की रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला। अब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति में निधि यादव को सदस्य नामित किया है। इससे पहले भी उन्हें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के पुनर्गठन के तहत गठित कॉस्ट नॉर्म समिति में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई थी। इस तरह केंद्र में लगातार दूसरी बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उत्तराखंड के पंचायतीराज विभाग के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है।

गांवों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने, पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक एवं संस्थागत क्षमताओं का विकास करने और ग्राम पंचायतों को अधिक जवाबदेह व सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में उत्तराखंड को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तराखंड शासन की पंचायती राज निदेशक निधि यादव को समिति का सदस्य नामित किया गया है।

**पांच वर्षों में खर्च होंगे 7,395.55 करोड़ रुपये**

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए मंजूरी दी है। योजना के तहत कुल 7,395.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 4,869.48 करोड़ रुपये तथा राज्यों की हिस्सेदारी 2,526.07 करोड़ रुपये होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत रूप से मजबूत बनाना, जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायतों को सशक्त, जवाबदेह एवं जनोन्मुखी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। यह पहल विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

**पालका साहनी की अध्यक्षता में गठित हुई समिति**

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, संयुक्त सचिव पालका साहनी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में मंत्रालय के निदेशक विपुल उज्ज्वल, रमित मौर्य, विजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ उप सचिव दीपेंद्र सिंह को सदस्य नामित किया गया है। वहीं, अवर सचिव पंकज कुमार को समिति का संयोजक बनाया गया है।

**पांच राज्यों के प्रतिनिधियों को मिला स्थान**

समिति में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि योजना के क्रियान्वयन में राज्यों के अनुभव और आवश्यकताओं को भी स्थान मिल सके। इसके तहत उत्तराखंड की निदेशक पंचायती राज IAS निधि यादव के अलावा आंध्र प्रदेश के आयुक्त वीआर कृष्ण तेजा मायलावरपु, बिहार के पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह, महाराष्ट्र के पंचायती राज विभाग के निदेशक गिरीश भालेराव तथा असम के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव अनंत कुमार गोगोई को सदस्य बनाया गया है।

**प्रशिक्षण से लेकर डिजिटल पंचायत तक पर रहेगा फोकस**

समिति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों के अनुरूप व्यापक क्रियान्वयन दिशा-निर्देश तैयार करना है। योजना के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, ऑनलाइन प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और विभिन्न राज्यों के अध्ययन भ्रमण जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, कंप्यूटर लैब, आधुनिक तकनीकी शिक्षण सुविधाओं तथा वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

**ग्रामसभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान**

योजना में ग्रामसभाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्कूलों एवं कॉलेजों में मॉडल युवा ग्रामसभा के आयोजन, ग्रामसभा अभिमुखीकरण और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पेसा) के तहत ग्रामसभाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेष सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामसभा मोबिलाइजर, पेसा समन्वयकों और सहायक समन्वयकों की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

योजना के अन्य महत्वपूर्ण घटकों में पंचायत भवनों से संबंधित पूर्व स्वीकृत कार्यों को पूरा करना, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों का गठन, ई-पंचायत मिशन, ग्राम मानचित्र (ग्राम मंचित्र) का उन्नयन, पंचायतों को प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता, शोध एवं प्रचार गतिविधियां तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

**स्थानांतरण के बाद केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी**

IAS निधि यादव को उत्तराखंड में निदेशक पंचायतीराज के दायित्व के दौरान किए गए कार्यों के बीच अब स्थानांतरण के उपरांत केंद्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दूसरी समिति में सदस्य बनाए जाने से उन्हें राज्यों के अनुभव और विशेष रूप से पर्वतीय प्रदेशों की जरूरतों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में रखने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, दूरस्थ गांवों की चुनौतियों और पंचायतों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

विभाग में नियुक्तियों से लेकर पदोन्नति, डिजिटलीकरण, महिला एवं बाल सहभागिता, प्रशिक्षण, वित्तीय आत्मनिर्भरता और पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन तक किए गए प्रयासों ने उत्तराखंड की पंचायतीराज व्यवस्था को नई दिशा देने का काम किया है। अब केंद्र में मिली दूसरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के अनुभवों को राष्ट्रीय पंचायत नीति और योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ने का अवसर भी मिला है।

**विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां, कार्मिक व्यवस्था को मिली मजबूती**

निदेशक IAS निधि यादव के कार्यकाल में पंचायतीराज विभाग की मानव संसाधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर नियुक्तियां की गईं। विभाग में 400 से अधिक नियुक्तियां होने से लंबे समय से कार्मिकों की कमी से प्रभावित कार्यों को गति देने में मदद मिली। पंचायतों से जुड़े प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के बेहतर संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

**25 वर्षों बाद ADO पंचायतों को पदोन्नति का अवसर**

विभागीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले 25 वर्षों में पहली बार सहायक विकास अधिकारी पंचायत से जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया रही। इससे विभागीय अधिकारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला और लंबे समय से लंबित पदोन्नति से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा। यह पहल विभागीय सेवा ढांचे को मजबूत बनाने के साथ कर्मचारियों के मनोबल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

**पंचायतों का डिजिटलीकरण, गांवों तक पहुंची डिजिटल व्यवस्था**

IAS निधि यादव के निर्देशन में पंचायतों को तकनीक से जोड़ने और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। विभागीय पोर्टल, ऑनलाइन कार्यप्रणाली, डिजिटल रिकॉर्ड और ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंचायतों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की पहल की गई। पंचायत प्रतिनिधियों को भी डिजिटल माध्यमों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की जानकारी, कार्यों का विवरण और प्रशासनिक प्रक्रियाएं तकनीक के माध्यम से संचालित हो सकें।

**महिला सभा और बाल सभा से मजबूत होगी ग्रामीण लोकतंत्र की नींव**

ग्राम पंचायतों में महिला सभा और बाल सभा का गठन स्थानीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। महिला सभाओं के माध्यम से महिलाओं को गांव के विकास, स्थानीय समस्याओं और निर्णय प्रक्रिया में अपनी बात रखने का मंच मिल रहा है। वहीं बाल सभाओं के जरिये बच्चों की आवश्यकताओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके अनुकूल गांव के विकास जैसे विषयों को पंचायतों के एजेंडे में शामिल करने का अवसर मिला है। इससे पंचायतों में महिलाओं और बच्चों की आवाज को संस्थागत मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

**परिसीमन से लेकर पंचायत चुनाव तक, ग्रामीण लोकतंत्र को मिली नई मजबूती**

निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पंचायत चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। परिसीमन के माध्यम से पंचायतों की संरचना को व्यवस्थित करने और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया गया। इसके साथ ही पंचायतों को उनकी स्थानीय जरूरतों और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप सशक्त बनाने के लिए विशेष एवं नवाचारी नीतियों पर भी काम किया गया।

**अलग नीतियों से पंचायतों को आत्मनिर्भर और जवाबदेह बनाने की पहल**

निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव के कार्यकाल में प्रदेश की पंचायतों को केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्थानीय विकास और सुशासन की मजबूत इकाई बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला सभा और बाल सभा का गठन, स्वयं के संसाधनों से राजस्व जुटाने की पहल, पंचायतों का डिजिटलीकरण, पंचायत विकास सूचकांक के माध्यम से प्रदर्शन का मूल्यांकन और प्रतिनिधियों का व्यापक प्रशिक्षण इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इन पहलों का उद्देश्य पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी रूप से सक्षम बनाते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता

**(शेष पृष्ठ 4 पर)**

( पृष्ठ 3 का शेष )

# उत्तराखंड पंचायतीराज का .....

विकसित करना है।

**पीडीआई रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर**

पंचायतों के विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए पंचायत विकास सूचकांक (PDI) को महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया गया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि, पशुपालन, बैंकिंग, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों के संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसी रैंकिंग में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला।

पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को बनाया क्षमता निर्माण का माध्यम

पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए केवल संसाधन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों का प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से विभाग ने ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। प्रदेश के 12 जनपदों के 89 ब्लॉकों में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 150 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई।

इस अभियान में 55,887 ग्राम पंचायत सदस्यों और 7,499 ग्राम प्रधानों को शामिल किया गया। इससे पहले 2,947 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 358 जिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। प्रशिक्षण में पंचायतीराज अधिनियम, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, ई-गवर्नेंस, विभागीय पोर्टल, पंचायत विकास सूचकांक और सुशासन से जुड़े विषय शामिल किए गए।

**नौ थीम पर विकसित गांवों की परिकल्पना**

प्रशिक्षण कार्यक्रम में नौ प्रमुख विषयों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इनमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव और महिला हितैषी गांव शामिल हैं। इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाना है।

**'प्रधान पति' परंपरा खत्म कर महिला नेतृत्व को बढ़ावा**

महिला पंचायत प्रतिनिधियों को वास्तविक नेतृत्व प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से विशेष प्रशिक्षण पहल भी की गई। दिसंबर 2025 में 'बदलाव का नेतृत्व - स्थानीय सुशासन और उसके परे महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना' विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें IAS निधि यादव ने स्पष्ट किया कि पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 'प्रधान पति' जैसी परंपराओं को समाप्त करना जरूरी है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वयं निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश की लगभग 19 हजार महिला पंचायत प्रतिनिधियों तक प्रशिक्षण पहुंचाने के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। कार्यक्रम में नेतृत्व कौशल, संवैधानिक अधिकार, ग्रामसभा की प्रक्रिया, पंचायत प्रशासन और महिला प्रतिनिधियों की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

**आत्मनिर्भर पंचायतों के लिए ह्रस्क्रपर जोर**

पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं के संसाधनों (ह्रस्क्र) से राजस्व संग्रहण और उसके उपयोग को भी विभाग ने प्राथमिकता दी। इस विषय पर 25 और 26 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पंचायतों को अपने स्तर पर राजस्व जुटाने, डिजिटल भुगतान, कर व्यवस्था, अभिलेखों के बेहतर प्रबंधन और स्थानीय विकास कार्यों में संसाधनों के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। IAS निधि यादव का विशेष फोकस रहा है कि पंचायतों की वास्तविक मजबूती के लिए उनका वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। स्वयं के संसाधनों से राजस्व जुटाने पर पंचायतें अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्य कर सकेंगी और केवल सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम होगी।

**पर्यावरण संरक्षण के लिए भी शुरू की गई पहल**

पंचायतीराज विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए भी पहल की गई। इसके तहत नव नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को आवंटित ग्राम पंचायतों में पौधरोपण सुनिश्चित करने से जुड़ी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। इसका उद्देश्य पंचायतों को विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित गांवों की परिकल्पना से जोड़ना है।

**पहली केंद्रीय समिति : RGSA के कॉस्ट नॉर्म तय करने की जिम्मेदारी**

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (क्रत्नस्) के पुनर्गठन और संशोधित योजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न घटकों के लागत मानक तय करने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति में उत्तराखंड की निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव को सदस्य बनाया गया था। समिति का दायित्व राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सुझावों के आधार पर योजना के विभिन्न घटकों के लिए संशोधित लागत मानकों का प्रस्ताव तैयार करना था। इसमें तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और उत्तराखंड के अधिकारियों को शामिल किया गया था।

दूसरी केंद्रीय समिति - PM-VGSY के दिशा-निर्देश तैयार करने में निभाएंगी भूमिका

अब केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए नई समिति गठित की है। इस समिति में उत्तराखंड की निदेशक पंचायतीराज IAS निधि यादव को सदस्य नामित किया गया है। समिति की अध्यक्षता मंत्रालय की संयुक्त सचिव पालका साहनी करेंगी। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। योजना का उद्देश्य पंचायतीराज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता बढ़ाना, जमीनी स्तर पर सुशासन मजबूत करना और पंचायतों को जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में विकसित करना है।

समिति प्रशिक्षण, पंचायत संसाधन केंद्रों, डिजिटल सुविधाओं, ग्रामसभा सशक्तीकरण, ई-पंचायत, ग्राम मंचित्र, पंचायतों को प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता जैसे विषयों पर व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगी। समिति को अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करनी हैं।

# सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा सेमन्या कण्वघाटी समाचार पत्र, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चला रहा जनजागरूकता मुहिम

**यातायात नियमों का पालन, राष्ट्रहित में बिजली बचाओ, पर्यावरण संरक्षण और साइबर अपराधों से सतर्क रहने का दे रहा संदेश; सम्पादक अवनीश कुमार के नेतृत्व में आमजन को जागरूक करने का प्रयास**

हरिद्वार। पत्रकारिता का दायित्व केवल समाचारों का प्रकाशन करना ही नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बदलाव की दिशा में पहल करना भी है। इसी सोच के साथ सेमन्या कण्वघाटी समाचार पत्र की ओर से सामाजिक सरोकारों से जुड़े चार महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक जनजागरूकता मुहिम संचालित की जा रही है। समाचार पत्र के सम्पादक अवनीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही इस मुहिम के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों का पालन करने, राष्ट्रहित में बिजली बचाने, पर्यावरण संरक्षण और बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।




इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को केवल संदेश देना नहीं, बल्कि उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे-छोटे प्रयासों से समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

**सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की अपील**

मुहिम के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और यातायात संकेतों का सम्मान करने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। अभियान का मूल संदेश है कि यातायात नियमों का पालन किसी कानूनी बाध्यता के साथ-साथ स्वयं और दूसरों के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है।

**राष्ट्रहित में बिजली बचाने का संदेश**

ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए समाचार पत्र की ओर से बिजली बचाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से जल रही लाइट, पंखे और अन्य विद्युत उपकरणों को बंद रखने की अपील की जा रही है। लोगों को ऊर्जा की बचत करने और बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुहिम का संदेश है कि बिजली की बचत केवल आर्थिक बचत नहीं, बल्कि राष्ट्र के ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है।

**पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों को कर रहा प्रेरित**

पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सेमन्या कण्वघाटी समाचार पत्र लगातार जागरूकता का संदेश दे रहा है। अभियान के माध्यम से पौधरोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक के कम उपयोग, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण भी जरूरी है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा।

**साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील**

डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया अकाउंट के दुरुपयोग जैसी घटनाओं को देखते हुए इस मुहिम में साइबर सुरक्षा को भी विशेष स्थान दिया गया है। लोगों को अनजान व्यक्तियों के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी और पासवर्ड साझा नहीं करने, संदिग्ध लिंक से बचने तथा ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सतर्कता बरतने का संदेश दिया जा रहा है। साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।

**समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है मुहिम का उद्देश्य-अवनीश कुमार**

सेमन्या कण्वघाटी समाचार पत्र के सम्पादक अवनीश कुमार का कहना है कि पत्रकारिता समाज का दर्पण होने के साथ-साथ समाज को दिशा देने का भी माध्यम है। समाचार पत्रों की जिम्मेदारी है कि वे जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाएं और लोगों को उनके नागरिक दायित्वों के प्रति जागरूक करें।उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन, बिजली की बचत, पर्यावरण संरक्षण और साइबर अपराधों से बचाव ऐसे विषय हैं, जिनका सीधा संबंध आम नागरिक के जीवन से है। इन विषयों पर जागरूकता के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। सेमन्या कण्वघाटी समाचार पत्र की ओर से संचालित यह मुहिम इसी दिशा में एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे।उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करे। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यातायात नियमों का पालन करे, बिजली बचाए, पर्यावरण की रक्षा करे और साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहे तो निश्चित रूप से एक सुरक्षित, स्वच्छ और जागरूक समाज का निर्माण संभव है।

सेमन्या कण्वघाटी समाचार पत्र की यह मुहिम पत्रकारिता को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से जागरूक, जिम्मेदार और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान देना है।



मा० पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

# सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण/आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आवासीय / गैर आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की जा रही हो तो कृपया भूमि क्रय करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी निम्न सूचनाओं/जानकारी का संज्ञान अवश्य लिया जाये :-

- प्राधिकरण के कार्य क्षेत्रान्तर्गत भूमि क्रय करने से पूर्व कृपया। एम.डी.डी.ए. कार्यालय से भूमि के भू-उपयोग की जानकारी अवश्य रूप से ली जाये। इस हेतु केता को कय की जाने वाली भूमि/भूखण्ड का वास्तुविद /ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया की-प्लान तथा भू-खण्ड के गूगल को-ऑर्डिनेट्स/भू-खण्ड की गूगल लोकेशन प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

- अवैध प्लाटिंगों पर कय किये गये भू-खण्ड पर एम.डी.डी.ए. द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।

- मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश तथा भवन उपविधि के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी के क्षेत्र से 30 मी० की दूरी के उपरान्त ही भूमि कय की जाये।

- प्राधिकरण से बिना स्वीकृति/अनुमति से की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भू-खण्ड कदापि कय न किया जाये। यदी सूचित होने के बावजूद भी भू-खण्ड कय किया जाता है तथा एम.डी.डी.ए. द्वारा भवन उपविधि के अनुसार प्रश्नगत अवैध प्लाटिंग के विरुद सील अथवा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केता की रहेगी। एम.डी.डी.ए.द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत की गयी अवैध प्लाटिंगों की भूमि के सम्बन्ध में सूचना/जानकारी एएम.डी.डी.ए. की ऑफिशियल वेबसाइट एमडीडीएओनलाइन-इन पर उपलब्ध है।

- जनहित में यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि/भू-खण्ड कय करने से पूर्व कय की जाने वाली भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजो का परीक्षण/सजरे के अनुसार भू-खण्ड खसरा न0 की स्थिति स्पष्ट करने/कय की जाने वाली भूमि में किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद होने अथवा न 1 न होने/कय की जाने वाली भूमि के रकबे में सरकारी भूमि सम्मिलित होने के सम्बन्ध में कृपया राजस्व विभाग से गली-माति परीक्षण कराया जाये।

- प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी उक्त सूचनाओं / जानकारी के कम में कय की गयी भूमि/भू-खण्ड का एम.डी.डी.ए. कार्यालय से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही मोके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

- क्रय की जाने वाली भूमि/भू-खण्ड के सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से भूमि/भू-खण्ड का प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्र की जानकारी प्राप्त की जाये कि जो भू-खण्ड केता द्वारा बिक्रेता से कय किया जा रहा है क्या वह भू-खण्ड स्वीकृत ले-आउट मानचित्र का भू-खण्ड का माग है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में भूमि विक्रेता से स्वीकृत ले-आउट मानचित्र/मानचित्र संख्या की जानकारी प्राप्त करते हुए उसका सत्यापन एम.डी.डी.ए. कार्यालय से अवश्य रूप से किया जाये।

**उक्त सूचना/जानकारी जनहित में जारी की जाती है।**

"आज्ञा से
उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण"
देहरादून।

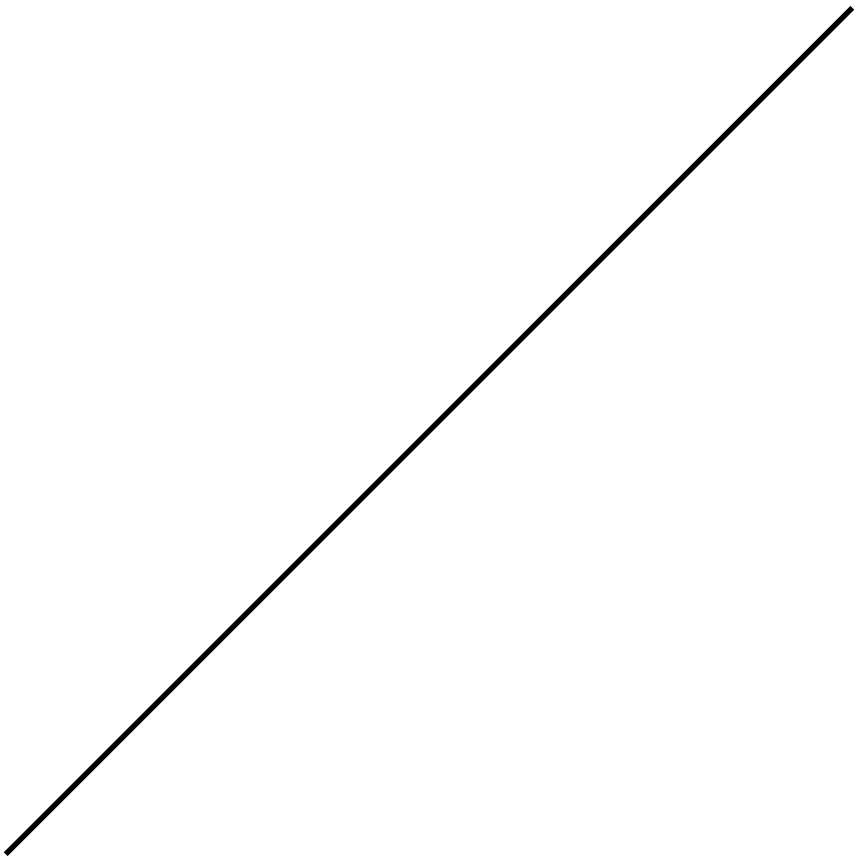

# मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
## लाया है

**देहरादून शहर में पहले आओं पहले पाओं स्कीम के तहत**

**अपने घर का सपना पूरा करने का एक सुनेहरा मौका।**

एम.डी.डी.ए. की ट्रांसपोर्ट नगर फेस–2, आई.एस.बी.टी. एवं आमवाला तरला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की आवसीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों हेतु पंजीकरण प्रारम्भः–

**HIG | MIG | STUDIO APARTMENT | L.I.G.**







| क्र. स. | फ्लैटों की श्रेणी | अनुमानित कीमत रू लाख में। | पंजीकरण धनराशि रू लाख में। | फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट) | फ्लैटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अल्प आय वर्ग (LIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़ | 22.90 | 2.30 | 582.82 | 60 |
| 2. | अल्प आय वर्ग (LIG 'C' Block) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़ | 23.29 | 2.32 | 582.82 | 16 |
| 3. | मध्यम आय वर्ग (MIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़ | 65.85 | 6.59 | 1503.40 | 112 |
| 4. | उच्च आय वर्ग (HIG) आलयम, सहस्त्रधारा रोड़ | 75.64 | 7.57 | 1877.83 | 112 |

| क्र. स. | फ्लैटों की श्रेणी | अनुमानित कीमत रू लाख में। | पंजीकरण धनराशि रू लाख में। | फ्लैट का अनुमानित सुपर एरिया (वर्ग फीट) | फ्लैटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | स्टूडियो अपार्टमेन्ट आलयम, सहस्त्रधारा रोड़ | 32.29 | 3.23 | 798.18 | 48 |
| 6. | अल्प आय वर्ग (LIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज–2 | 19.90 | 2.00 | 453.53 | 97 |
| 7. | मध्यम आय वर्ग (MIG) ट्रांसपोर्ट नगर, फेज–2 | 49.50 | 4.95 | 1090 | 27 |
| 8. | उच्च आय वर्ग (HIG) आई.एस.बी.टी. | 71.50 | 7.15 | 1954 | 130 |

**विशेष छूट :-**

1. उक्त भवनों में एक मुश्त धनराशि जमा किये जाने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
2. यदि काई महिला/सिनियर सिटिजन/दिव्यांग इस हेतु आवेदन करे तो उनको 01 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट उनको पूर्ववत 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के उपरान्त अवशेष देय धनराशि प्रदान की जायेगी।

**आलयम आवसीय योजना**

की जानकारी हेतु

मो. **8006409136**

**आई.एस.बी.टी./ट्रांसपोर्ट नगर**

आवसीय योजना की जानकारी हेतु

मो. **9193639595**

## मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

**सहारनपुर रोड़, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून । फोन : 0135-663150**

E mail: info.mdda@mddaonline.in Website : www.mddaonline.in

पंजीकरण फॉर्म प्राधिकरण के साइट ऑफिस, कार्यालय व नीचे दिये गए बैंक की शाखओं में भी उपलब्ध है।

# RAIN WATER HARVESTING

## रेन वाटर हार्वेस्टिंग

बादल के गुब्बारों
की बूंद-बूंद संभालो,
कुदरत की इस दौलत का
तुम लाभ उठा लो



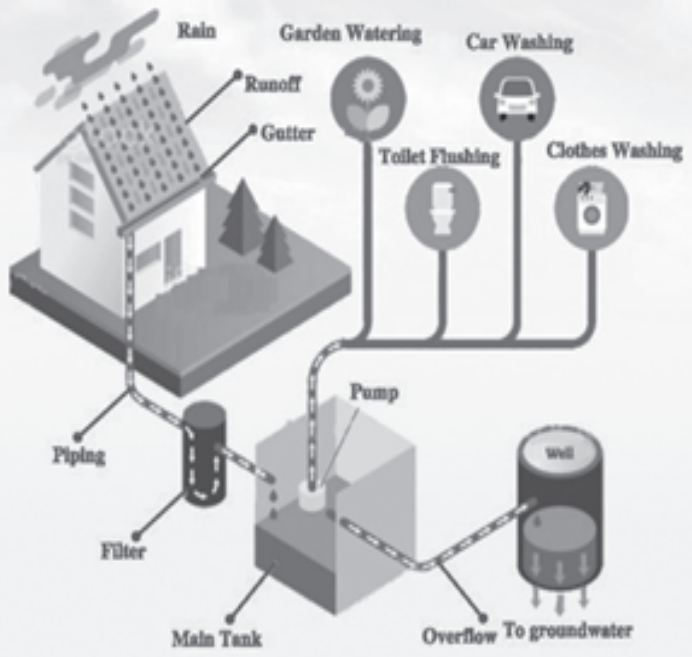


## वर्षा जल संग्रहण के लाभः-

- मानसून सीजन से अतिरिक्त सीजन्स में जल की उपलब्धता बनाये रखने में।
- सूखे की समस्या से निपटने में।
- भूमिगत जल की स्थिति को सुधारन में।
- सस्टेनेबल वॉटर सप्लाई की और एक कदम
- शहर की जल आपूर्ति पर बढते दबाब को घटाने में
- सामूहिक रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को उपयोग में लाने से शहर के ड्रेनेज सिस्अम पर बढते दबाव को कम किया जा सकता है, जिससे बाढ एवं भू-क्षरण की समस्या का नियंत्रण किया जा सकता है।

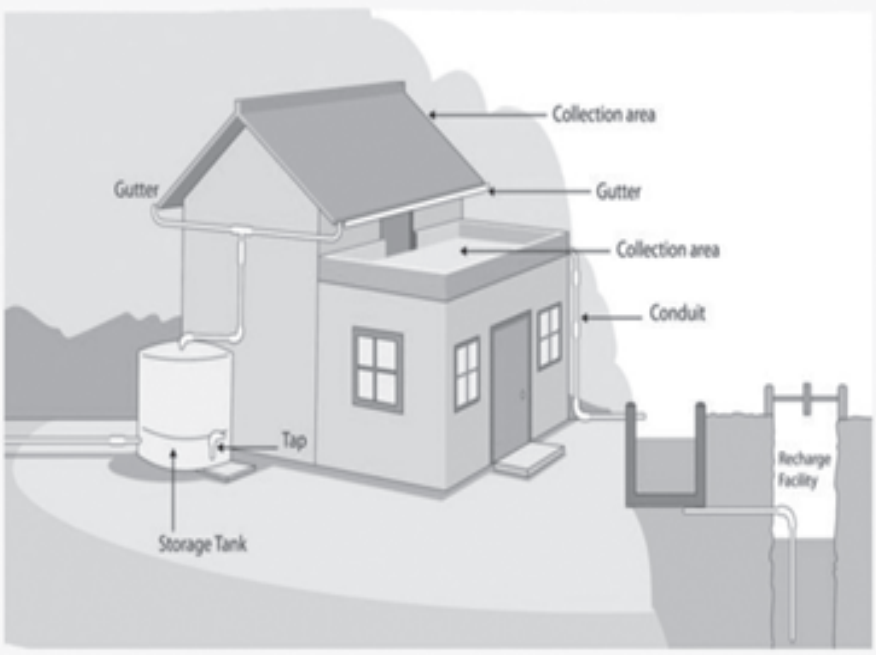


## रख-रखाव के तरीकेः-

- छत की सफाई हमेशा करें।
- रेन सेपरेटर का कैप तभी खोलें जब वर्षा बंद हो जाये। वर्षा जल के बह जाने के बाद उसे बंद कर दें।
- फिल्टर को हमेशा साफ रखें।
- टैंक की सफाई हर 06 माह के अंतराल पर जरूरी है।

*... Save it for another day!*









## DID YOU KNOW

**ONLY 8% OF FALL RAINWATER IS COLLECTED IN INDIA**

For More Information Contact Your Architector visit : http://mddaonline.in/

**MDDA, DEHRADUN**
(Mussoorie Dehradun Development Authority, Dehradun)
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
(An ISO Certified Authority)

# आलिया भट्ट ने छठी क्लास में शुरू कर दी थी डेटिंग



एक्ट्रेस आलिया भट्ट पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण में कई बार आ चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने इस चैट शो में 2013 में अपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के को-स्टार्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ डेब्यू किया था। इस एंटरटेनिंग एपिसोड के दौरान, आलिया ने होस्ट और फिल्ममेकर करण जौहर समेत सभी को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने क्लास 6 में डेटिंग शुरू कर दी थी।

करण ने कहा कि वरुण ने उन्हें बताया कि आलिया के बचपन में कई यंग बॉयफ्रेंड थे।

हालांकि, इस पर मजाकिया अंदाज में आपत्ति जताते हुए आलिया ने कहा, मैं इसे कोई सिलसिला नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे (बॉयफ्रेंड) और सीरियस रिलेशनशिप थे, जैसे दो साल, (फिर) दो साल।

करण ने इस बात पर हैरानी जताई कि आलिया 17 साल की उम्र तक दो सीरियस रिलेशनशिप में रह चुकी थीं। करण जौहर ने पूछा, आपने 10 साल की उम्र में डेटिंग शुरू कर दी थी?

आलिया ने हंसकर जवाब देते हुए कहा, इसीलिए मैं कहती हूं कि यह कोई डोरी नहीं है। मैंने छठी क्लास में डेटिंग शुरू कर दी थी।

जब हैरान करण ने उनसे पूछा, क्या?, आलिया ने जवाब दिया, लेकिन, जाहिर है कि यह डेटिंग नहीं थी। यह तो बस ऐसा था, जैसे हम क्लासरूम की दूसरी तरफ से एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे।

वरुण ने फिर मजाक में कहा कि यह आधा-आधा था, जिस पर आलिया ने कहा, कुछ भी आधा-अधूरा नहीं था। असल में मेरा पहला बॉयफ्रेंड 10वीं क्लास में था। यह बताते हुए कि यह एक सीरियस रिलेशनशिप था, आलिया ने कहा, क्योंकि मैंने उसे दो साल तक डेट किया। वह मेरा पहला, हाई-स्कूल जैसा प्यार था।

करण ने आलिया से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने उन्हें इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि वह एक्टर बनना चाहती थीं। इस बात से इनकार करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आलिया की लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 14 अप्रैल, 2022 को एक्टर रणबीर कपूर से शादी कर ली।

नवंबर 2022 में इस लवबर्ड्स ने अपनी बेटी राहा कपूर का स्वागत किया।

## मित्रता के बाद अब पार्टी एनिमल्स में नजर आएंगे विराज घेलानी



एक्टर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर विराज घेलानी अपनी नई फिल्म पार्टी एनिमल्स के साथ दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं। दोस्ती, मस्ती और गलत फैसलों के चलते एक रात की कहानी पर बनी इस कॉमेडी फिल्म में विराज लीड रोल में नजर आएंगे। एक्टर ने फिल्म को फुल-ऑन मस्ती फिल्म बताया है। उनका कहना है कि इसमें दोस्ती, पागलपन और ऐसे हालात देखने को मिलेंगे, जो हर पल और मजेदार होते जाएंगे। विराज ने फिल्म को लेकर कहा, पार्टी एनिमल्स एक अलग तरह की फिल्म है। यह फुल-ऑन मस्ती फिल्म है। मैं काफी एक्साइटेड हूं कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें। इसमें दोस्ती, पागलपन और ऐसे हालात हैं, जो लगातार और ज्यादा मजेदार होते जाते हैं। फिल्म की दुनिया में काफी एनर्जी है और दर्शक इससे खुद को जोड़ पाएंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि सभी इसे सिनेमाघरों में देखें। यूडली फिल्म्स के बैनर तले बनी पार्टी एनिमल्स की कहानी मुंबई में सेट है। फिल्म में विराज घेलानी, मान पटेल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अर्जुन तनवर अरमान खन्ना के रोल में नजर आएंगे। दोनों बचपन के दोस्त हैं, जो एक रात पार्टी करने के लिए मिलते हैं। लेकिन उनकी यह मुलाकात जल्द ही मुश्किलों में बदल जाती है। रोमांटिक उलझनें, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े और बिगड़ी परिस्थितियों को संभालने की उनकी कोशिशें मामले को और उलझा देती हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद कुमार ने कहा, यह फिल्म बिना किसी झिझक के पागलपन, बेबाकी और अपने ही मजाक को समझने वाले अंदाज में आगे बढ़ती है। हम यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि फिल्म के किरदारों का हर फैसला सही है।

## येलो गाउन, डीप नेकलाइन और कातिलाना अदाएं, पलक तिवारी की तस्वीरों ने मचाया तहलका



बॉलीवुड की यंग, ग्लैमरस और स्टनिंग एक्ट्रेस पलक तिवारी अपने हर अंदाज से फैंस को सरप्राइज करना बखूबी जानती हैं। पलक सोशल मीडिया पर हमेशा अपने स्टाइलिश लुक्स से तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर बेहद आकर्षक तस्वीरें शेयर की हैं।

पीले रंग के बैकड्रॉप और मैचिंग आउटफिट में पलक का यह नया अवतार इस समय इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरों में उनकी फिटनेस, स्टाइल सेंस और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

तस्वीरों में पलक तिवारी ने ब्राइट येलो कलर की एक बेहद खूबसूरत गाउन पहनी हुई है। इस आउटफिट का अपर सेक्शन एक स्ट्रक्चर्ड कॉर्सेट बस्टियर डिजाइन में तैयार किया गया है, जिसमें फ्रंट पर डेलिकेट लेस-अप डिटेलिंग दी गई है।

ड्रेस के स्लीक नूडल स्ट्रैप्स और डीप प्लंजिंग नेकलाइन पलक के शोल्डर लाइन और कॉलरबोन को परफेक्टली हाइलाइट कर रहे हैं। ड्रेस का लोअर पार्ट यानी स्कर्ट का हिस्सा भी बेहद खास है। कमर से रैप-अराउंड स्टाइल में शुरू होने वाला यह गाउन नीचे फ्लोइंग रफल्स और लेयर्स के साथ आता है। इसके साथ ही ड्रेस में दिया गया बोल्ड और हाई-थाई स्लिट पलक के लेग्स को फ्लॉन्ट कर रहा है।

अपने इस बोल्ड आउटफिट को बैलेंस करने के लिए पलक ने मेकअप को बहुत ही सटल और क्लासी रखा है। उन्होंने ब्रॉन्ज और ब्राउन टोन वाली स्मोकी आइज के साथ विंग्ड आईलाइनर का इस्तेमाल किया है।

पलक ने अपने लंबे और घने बालों को हाफ-अप, हाफ-डाउन स्टाइल में बांधा हुआ है, जिसमें से कुछ लहराती हुई मेसी लटें उनके चेहरे पर आ रही हैं। यह मेसी वेवी टेक्सचर उनके ओवरऑल लुक को एक सॉफ्ट लेकिन अट्रैक्टिव वाइब दे रहा है।

उनके फेशियल एक्सप्रेशन्स की बात करें तो कैमरे के सामने पलक का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है। कभी वे कैमरे की तरफ इंटेंस और सेडक्टिव लुक देती नजर आ रही हैं, तो कभी अपनी उंगलियों से होंठों और चेहरे को सहलाते हुए सेंसुअस एक्सप्रेशन्स दे रही हैं। पलक तिवारी की इन तस्वीरों के शेयर होते ही फैंस और सेलेब्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स कमेंट सेक्शन में उन्हें येलो क्वीन, सनशाइन गर्ल, स्टनिंग और एब्सोल्यूट गॉर्जियस कहकर बुला रहे हैं।

## इमरान हाशमी की हॉरर फिल्म रूह का मोशन-पोस्टर जारी, 2027 में तीन भाषाओं में होगी प्रदर्शित

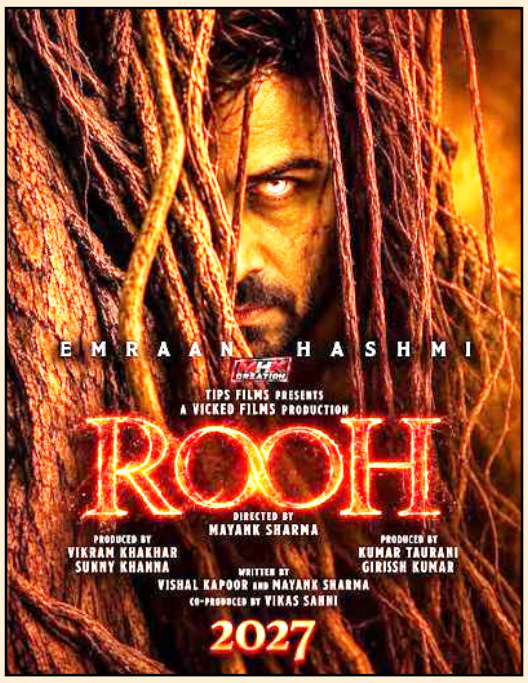


अभिनेता इमरान हाशमी की आगामी संगीतमय हॉरर फिल्म 'रूह' का पहला प्रचारात्मक चलचित्र पोस्टर निर्माताओं ने सामाजिक माध्यमों पर जारी कर दिया है। फिल्म की घोषणा इसी साल जून में की गई थी। मयंक शर्मा के निर्देशन में बनी यह रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्म इमरान हाशमी की हॉरर फिल्मों में वापसी मानी जा रही है। इमरान इससे पहले 'राज 2' और 'एक थी डायन' जैसी फिल्मों में डरावनी भूमिकाओं के जरिए दर्शकों के सामने आ चुके हैं। 'रूह' का निर्माण टिप्स फिल्म्स और विकेड फिल्म्स के सहयोग से किया जा रहा है। फिल्म की पटकथा मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने संयुक्त रूप से लिखी है।

जारी किए गए प्रचारात्मक चलचित्र पोस्टर में एक घना और रहस्यमयी जंगल दिखाई देता है। इसी जंगल में एक पेड़ के पीछे इमरान हाशमी लंबे बालों और डरावने अंदाज में नजर आते हैं। पोस्टर के साथ सुनाई देने वाला तेज और भयावह संगीत फिल्म के डरावने माहौल को और प्रभावशाली बनाता है। इसके साथ निर्माताओं ने संदेश दिया है, 'डर जितना गहरा होगा, संगीत उतना ही बड़ा होगा।'

फिलहाल फिल्म की कहानी और अन्य कलाकारों से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखा गया है। निर्माताओं के अनुसार, 'रूह' वर्ष 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म के पहले पोस्टर के जारी होने के बाद दर्शकों में इसके कथानक और संगीत को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

# सिर की खुजली से परेशान हैं? इन 5 प्राकृतिक तरीकों से पाएं राहत



सिर की खुजली एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह समस्या सिर में खुजली, जलन और कभी-कभी त्वचा पर लालिमा भी ला सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रूसी, गंदगी का जमा होना या एलर्जी। इस लेख में हम आपको कुछ प्राकृतिक उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपनी सिर की खुजली का इलाज कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं।

**नारियल तेल का उपयोग करें**

नारियल तेल एक प्राकृतिक नमी देने वाला है, जो आपके सिर को नमी प्रदान करता है और खुजली को कम करता है।

इसे उपयोग करने के लिए थोड़े-से नारियल तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे अपने सिर पर अच्छी तरह लगाएं। 30 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें, फिर सामान्य शैंपू से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में 2 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले।

**एलोवेरा जेल लगाएं**

एलोवेरा जेल में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो खुजली वाले सिर को आराम पहुंचाते हैं।

इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और इसे अपने सिर पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे पानी से धो लें।

यह उपाय आपके सिर की त्वचा को ठंडक देगा और खुजली को कम करेगा। एलोवेरा जेल का नियमित उपयोग आपके सिर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।

नीम का तेल लगाएं

नीम का तेल कीटाणु नाशक और फंगल संक्रमण को रोकने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो रूसी और खुजली का कारण बन सकते हैं।

इसे उपयोग करने के लिए नीम के तेल को नारियल तेल के साथ मिलाकर हल्का गर्म करें, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं और मसाज करें। 30 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे पानी से धो लें। यह उपाय हफ्ते में 1 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले।

**दही का मास्क लगाएं**

दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके सिर की त्वचा को पोषण देते हैं और खुजली को कम करते हैं।

इसके लिए थोड़ी दही लें और उसमें नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद इसे पानी से धो लें। यह उपाय हफ्ते में 2 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले। दही का नियमित उपयोग आपके सिर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।

**सेब का सिरका लगाएं**

सेब का सिरका आपके सिर के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे खुजली कम होती है। इसके लिए एक कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं, फिर इसे अपने सिर पर स्प्रे करें और हल्का मसाज करें। 5-10 मिनट तक छोड़ने के बाद इसे पानी से धो लें। यह उपाय हफ्ते में 1 बार करें ताकि आपको जल्द राहत मिले। इन सभी उपायों का नियमित उपयोग करके आप अपनी खुजली वाले सिर का इलाज कर सकते हैं।

# बच्चों को नए खाने की आदत डालने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स



बच्चों को नए खाने की चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, खासकर जब वे खाने में नखरे करते हों। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके के बारे में जानेंगे, जो बच्चों को नए खाने की चीजों को आजमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन तरीकों का उपयोग करके आप अपने बच्चे को पोषण से भरपूर आहार देने में मदद कर सकते हैं।

**रंग-बिरंगे व्यंजन बनाएं**- बच्चों को रंग-बिरंगे और आकर्षक दिखने वाले व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। आप अपने खाने में अलग-अलग रंगों के फल और सब्जियां शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गाजर, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च आदि का उपयोग करके सलाद बना सकते हैं या शेक में विभिन्न रंगों के फलों का मिश्रण कर सकते हैं। इससे न केवल खाना देखने में अच्छा लगेगा बल्कि बच्चे भी इसे आसानी से खा लेंगे और नए स्वादों का आनंद ले पाएंगे।

**खेल-खेल में सिखाएं**- बच्चों को नए खाने की चीजें आजमाने के लिए खेल-खेल में सिखाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप उन्हें अपनी प्लेट पर अलग-अलग आकार और रंग की सब्जियां देकर पूछ सकते हैं कि वे कौन-सी सब्जी सबसे पहले खाना चाहेंगे। इसके अलावा आप उन्हें खाना बनाते समय भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों को काटने या सलाद बनाने में उनकी मदद लें। इससे उनका ध्यान भटका रहेगा और वे नया खाना खुशी-खुशी खा लेंगे।

**छोटे-छोटे हिस्से दें**- बच्चों को छोटे-छोटे हिस्से देकर नए खाने की चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करें। बड़े हिस्से देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं या खाने में अनिच्छा दिखाते हैं। इसलिए शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे हिस्से दें ताकि वे आसानी से खा सकें और धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकें। इसके अलावा छोटे हिस्से देने से वे नए स्वादों का आनंद ले पाएंगे और धीरे-धीरे नए खाने की आदत डाल सकेंगे। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

**कहानी सुनाएं**- बच्चों को खाने में रुचि दिलाने के लिए कहानियों का सहारा लें। आप उन्हें बता सकते हैं कि किसी खास फल या सब्जी की कहानी क्या है, इससे उनका ध्यान उस खाने पर केंद्रित होगा। उदाहरण के लिए, आप बता सकते हैं कि गाजर आंखों के लिए फायदेमंद होती है या पालक खाने से ताकत मिलती है। इस तरह की कहानियों से बच्चे नए खाने की चीजों को आजमाने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं।

**खुद उदाहरण बनें**- बच्चे अक्सर अपने माता-पिता से सीखते हैं इसलिए अगर आप खुद नए खाने की चीजें खाएंगे तो वे भी आपका अनुसरण करेंगे। अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाएं और उन्हें दिखाएं कि आप खुद भी नए स्वादों का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा जब बच्चे आपको कुछ नया खाते हुए देखेंगे तो वे भी उसे आजमाने में दिलचस्पी दिखाएंगे। इस तरह आप अपने बच्चे को पोषण से भरपूर आहार देने में सफल हो सकते हैं।

# थकान और तनाव से पाना है छुटकारा तो करें दोलासन, जानें इसके फायदे




नई दिल्ली ।आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में योग एक ऐसी प्राचीन पद्धति है, जो न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। योग के इन्हीं आसनों में दोलासन का विशेष महत्व है। दोलासन दो शब्दों से मिलकर बना है, दोल यानी झूलना और आसन यानी मुद्रा। इस आसन को करने के दौरान शरीर झूले के समान आगे-पीछे झूलता है। यह आसन खासतौर पर पेट, पीठ और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, दोलासन (पेंडुलम या झूलने की मुद्रा) एक गतिशील योगासन है। इसका नियमित अभ्यास थकान, सिरदर्द और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है।

दरअसल, इस आसन को करने के दौरान अभ्यासकर्ता आगे-पीछे की ओर सिर को झुकाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है और दिमाग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। इससे सिरदर्द में आराम मिलता है और दिनभर की थकान कम होती है। साथ ही, इस दौरान शरीर की स्ट्रेचिंग होने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है और मन शांत होता है, जिससे चिंता और तनाव जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

दोलासन से पेट और कोर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। इस आसन को करने के दौरान अभ्यासकर्ता के पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव और दबाव पड़ता है, जिससे वे सक्रिय होती हैं। इस प्रक्रिया से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। साथ ही, कोर मसल्स मजबूत होने से शरीर का संतुलन और पोस्चर बेहतर होता है, और कमर दर्द की समस्या में भी राहत मिलती है।

जिन्हें गंभीर कमर दर्द या स्लिप डिस्क की समस्या है, वे इस आसन को न करें क्योंकि इसमें आगे झुकना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) या चक्कर आने की समस्या वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए।

# सर्दियों में भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनने वाली महिलाएं इन तरीकों से करें लेयरिंग



सर्दियों में भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनने वाली महिलाएं अक्सर ठंड से बचने के लिए कई परतें पहनती हैं। हालांकि, सही तरीके से लेयरिंग न करने पर यह देखने में अच्छा नहीं लगता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप सर्दियों में भी स्टाइलिश और आरामदायक रह सकती हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पारंपरिक लुक को और भी खास बना सकती हैं और ठंड से भी बच सकती हैं।

**कुर्ता और कोट का मेल**

सर्दियों में कुर्ता पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए आप एक सुंदर कोट का इस्तेमाल कर सकती हैं।

अगर आप प्रिंटेड कुर्ता पहन रही हैं तो सादे रंग का कोट चुनें। वहीं, अगर आपका कुर्ता सादे रंग का है तो प्रिंटेड कोट बेहतर रहेगा।

इससे न केवल आपका लुक बेहद खास लगेगा, बल्कि ठंड से भी अच्छी तरह बचाव हो जाएगा।

**साड़ी के साथ शॉल पहनें**

साड़ी के साथ शॉल पहनना एक शानदार तरीका है, जिससे आप ठंड से बच सकती हैं और स्टाइलिश भी दिख सकती हैं।

शॉल को आप अपने कंधों पर डाल सकती हैं या इसे अपनी साड़ी के पल्लू की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।

यह न केवल आपको गर्म रखेगा, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाएगा। अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की शॉल चुनकर आप अपने साड़ी लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।

अनारकली सूट और जैकेट का मेल

अनारकली सूट हमेशा से ही पारंपरिक और आकर्षक रहा है। सर्दियों में इसे और भी खास बनाने के लिए आप एक सुंदर जैकेट का इस्तेमाल कर सकती हैं।

जैकेट न केवल आपको गर्म रखेगी, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाएगी। आप अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की जैकेट चुन सकती हैं, ताकि आपका अनारकली सूट और जैकेट का मेल शानदार लगे।

इस तरह से आप ठंड से बचते हुए भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

# प्रदेश में बढ़ रहा भ्रष्टाचार : राजाराम

**हरिद्वार** । बसपा की बैठक का आयोजन शिवालिक नगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी राजाराम ने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है और जनता का झुकाव बसपा की तरफ बढ़ रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देश पर कार्य करे और आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी की जीत के लिए बूथ स्तर तक मेहनत करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को बसपा से बहुत उम्मीद है। 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर लक्सर क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क करे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद शामिल रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी ने कहा कि सर्व समाज की भागीदारी से प्रदेश सरकार बनेगी। सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। विधायक मो. शहजाद ने कहा कि प्रदेश सरकार जातीय और धार्मिक भेदभाव पैदा कर आपसी भाईचारा समाप्त कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दिशा निर्देश पर कार्य करके प्रदेश में सरकार बनानी है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम, पवन पाल, सतेंद्र सिंह, अनूप सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष सूरज मल, मुकेश कर, प्रवीण कुमार, धीरसिंह बिष्ट, आदेश कुमार, इरशाद, वीर सिंह गौतम, डॉ शमशाद, यासर अराफात, राव अखलाक, दीपक गौतम, सुरेश कुमार, विश्वास कुमार आदि उपस्थित रहे।

# बाल अपराध, नशे और साइबर अपराध से बचाव के प्रति किया जागरूक

**हरिद्वार** । बहादपुरजट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें पीएलवी माहेश्वरी और विनोद कुमार ने छात्र-छात्राओं को बाल अपराध, नशे की रोकथाम, साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम और महिला अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने, अनजान लोगों से ओटीपी साझा न करने और संदिग्ध कॉल की सूचना पुलिस को देने की अपील की। साथ ही बताया कि प्राधिकरण गरीब, असहाय, महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को नि:शुल्क अधिवक्ता सेवा उपलब्ध कराता है। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह चौहान ने शिविर को सराहनीय पहल बताया।इस दौरान सतीश शास्त्री, अनुपमा चौहान, वीर सिंह, शाहिद अली, कलीम अंसारी, अनीता चौहान, अरुणा यादव, सुदेश चौहान, अजय यादव, सुरेंद्र कुमार, पूजा जोशी और अंजू रानी मौजूद रहे।

# बस स्टैंड के पास नाबालिग आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो वायरल

**हरिद्वार** । हरिद्वार बस स्टैंड के पास देर रात नाबालिग किशोर के दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। वायरल वीडियो में कई नाबालिग किशोर एक अन्य किशोर को घेर कर लाठी-डंडों से पीटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। पुलिस के अनुसार, दो नाबालिगों के वाहनों के आपस में टकराने के बाद विवाद शुरू हुआ था। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शुक्रवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच की गई। जांच के बाद नाबालिगों को हिरासत में लिए गया। काउंसिलिंग और मारपीट नहीं करने की हिदायत के बाद सभी को परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

# बादलों से धूप की तपिश कम रही, दिन में ठंड का अहसास बना रहा

**हरिद्वार** । धर्मनगरी में शुक्रवार को आसमान में बादल छाने से धूप की तपिश कम रही। सुबह से शाम तक चमक फीकी रहने से पूरा दिन मौसम में ठंडक का एहसास बना रहा। बादलों की वजह से दिन में ठंड का एहसास बढ़ गया। वहीं अधिकतम तापमान में भी आधा डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के आंकड़ों के अनुसार धर्मनगरी में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। जबकि न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मौसम में आए इस बदलाव से दिन में ठंडक और रात में हल्की राहत महसूस हुई।

# नशे से दूर रहें, कानूनी अधिकारों के प्रति भी जागरूक बनें छात्र

**हरिद्वार** । नशे की लत से बचाव और कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को श्यामपुर के राजकीय इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज में अलग-अलग विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। दोनों शिविरों में कुल 344 छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों, पुनर्वास की सुविधाओं और नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बाल दिवस विशेष अभियान के तहत आयोजित इन शिविरों में पैरा लीगल वालंटियर एम. कुमार सूर्या ने कहा कि नशे की लत युवाओं के भविष्य के साथ उनके परिवार को भी प्रभावित करती है।

# कुम्भ-2027: हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाएं होंगी पुख्ता

**- रेलवे की व्यवस्थाओं पर हुआ विस्तृत मंथन**

**- मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं को परखने पर जोर**



**हरिद्वार** । कुम्भ मेला-2027 में श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिसे देखते हुए हरिद्वार स्टेशन के साथी आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं के विस्तार से लेकर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित आवागमन तक, सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को मेलाधिकारी सोनिका, आईजी (कुम्भ) डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की मंडलीय रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी (कुम्भ) आयुष अग्रवाल ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही, सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। यात्री सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन, ट्रेन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श भी हुआ।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नवनिर्मित अनारक्षित टिकट केंद्र, प्रतीक्षालय, होल्डिंग एरिया और यात्री आवागमन के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं को देखा। रेलवे अधिकारियों ने मेले के दौरान संभावित यात्री संख्या के अनुरूप की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मेलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार कुंभ में पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ ही भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाएं ठोस, व्यावहारिक और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। यात्रियों के प्रवेश, निकास, ठहराव और आवागमन की स्पष्ट और त्रुटिरहित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी प्रस्तावित व्यवस्थाओं को मॉक ड्रिल के जरिए परखा जाए, तथा संभावित आकस्मिक स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भी समुचित रखी जाय।

पुलिस अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में पर्याप्त पार्किंग सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया, ताकि वाहन सड़कों पर खड़े न हों और यातायात बाधित न हो। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंध करने तथा यात्रियों की सुरक्षित निकासी के लिए अधिकाधिक निकास मार्ग उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।

आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के अलग-अलग प्रवेश मार्ग निर्धारित करने पर विचार हुआ। विभिन्न दिशाओं और क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए पृथक प्रस्थान व्यवस्था विकसित करने पर भी सहमति बनी। इससे आवाजाही व्यवस्थित होगी और भीड़ का अनावश्यक दबाव घटेगा।

अधिकारियों ने कहा कि ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान के समय, यात्रियों की संख्या और स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल रखा जाए, ताकि एक ही समय में अत्यधिक भीड़ जमा न हो। यात्री दबाव के अनुरूप ट्रेनों के संचालन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की योजना बनाने पर भी जोर दिया गया।

इस दौरान यह भी तय किया गया कि निरीक्षण में सामने आए व्यावहारिक सुझावों और सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद इसे मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साझा कर आपसी समन्वय से तय किया जाएगा, ताकि कुम्भ मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हो सकें। निरीक्षण के दौरान उत्तर रेलवे के ओएसडी (कुंभ) राजीव रंजन 'राजू' , सीनियर डिवजीनल कॉमर्शियल मैनेजर महेश यादव, सीनियर डिवीजनल इंजीनियर तेजवीर सिंह, हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट हर गिरि , अपर पुलिस अधीक्षक (कुम्भ) राजेश भट्ट, अपर पुलिस अधीक्षक (संचार) विपिन कुमार, सीओ जीआरपी अनुज कुमार सहित मेला प्रशासन, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के अनेक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

# भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

**हरिद्वार** । भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने हरिद्वार में हस्ताक्षर अभियान चलाया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक मायापुर एवं जिला महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कृषि मंत्री गणेश जोशी, महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से जवाब मांगा गया। जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मंच से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जब सवाल उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों तक पहुंचते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का एक-एक रुपये का हिसाब सरकार को देना चाहिए। जिन सरकारी फैसलों पर सवाल उठे हैं, उनकी मंजूरी, भुगतान और जांच का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। ब्लॉक अध्यक्ष अजय गिरी और पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए तमाम दस्तावेज मांगती है, ऐसे में मंत्रियों के विभागों के फैसलों और भुगतान का हिसाब मांगना गलत कैसे हो सकता है। महानगर कांग्रेस कोषाध्यक्ष ओम मलिक और सचिव करन सिंह राणा ने सहकारी समितियों के कामकाज की स्वतंत्र जांच और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं ब्लॉक कोषाध्यक्ष गौरव गोस्वामी और रूपांशु प्रधान ने आरोपों की समयबद्ध जांच, सरकारी अभिलेख सार्वजनिक करने तथा दोषियों से सरकारी धन की वसूली की मांग उठाई। अभियान में पार्षद सुनील कुमार सिंह, प्रदीप वर्मा, संदीप सिंह, सचिन पाल, मोहित अरियाल, मोहित, आशुतोष, रोहित, अंशु, कुनाल निषाद, हर्ष यादव, मानव, केशव ठाकुर, जतिन बब्बर, मोहित बब्बर, हिमांशु, गौरव, कुलदीप, शिवम यादव, सन्नी कुमार, रमेश कुमार, देवांग पंवार, निशांत सचदेवा, आदित्य चंचल, सचिन कुमार, राजू, मनीष बंसल अतुल गिरी, तरनजीत सिंह और उपेंद्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

स्वामी,मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स,इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड़) से प्रकाशित किया।

**सम्पादक: अवनीश कुमार, मो०** 9410553400

ई-मेल: liveskgnews@gmail.com

**( सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा )**

**सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नही है।**